प्रेषक,

शेषनाथ,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2023

विषय:- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2022-23 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू.900.00 करोड़ (रूपए नौ अरब मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू.450.00 करोड़ (रूपए चार अरब पचास करोड़ मात्र) को अन्तिम किश्त के रूप में स्वीकृत/अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के पत्र संख्या-2833/ यू.पी.एफ./प्र.प्र.(लेखा)/बजट-2023-24 दिनांक 13.06.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2022-23 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू.900.00 करोड़ (रूपए नौ अरब मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू.450.00 करोड़ (रूपए चार अरब पचास करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या:4/2023/ I/311788/2023-46-2002-003-2-2023, दिनांक 03.05.2023 के द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में गन्ना मूल्य भुगतान मद में प्राविधानित धनराशि रू.900.00 करोड़ (रूपए नौ अरब मात्र) के सापेक्ष, अवशेष धनराशि रू.450.00 करोड़ (रूपए चार अरब पचास करोड़ मात्र) को अन्तिम किश्त के रूप में स्वीकृत करने तथा उक्त का व्यय गन्ना मूल्य भुगतान मद में किये जाने की, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि आप कृपया वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 के पैरा-223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के पेराई सत्र 2022-23 के बकाया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

गन्ना मूल्य भुगतान हेतु, प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा, एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि उसी कार्य के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गयी है।

(4) राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षों में की जाएगी।

(5) ब्याज की दर 14 प्रतिशत (11.50+2.50) वार्षिक होगी तथा नियमित अदायगी पर 2.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(6) मूलधन/ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

(7) मूलधन एवं ब्याज की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगांठ तिथि को की जानी होगी।

(8) उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

(9) संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें:-

(i) कोषागार का नाम-

(ii) चालान संख्या तथा दिनांक-

(iii) जमा धनराशि किश्त ब्याज

(iv) लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज

(v) शासनादेश संख्या और एस.एल.आर. का सन्दर्भ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(vi) पिछले जमा का सन्दर्भ

(10) चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराऐं।

(11) भविष्य में शासन द्वारा स्वीकृत ऋण तभी अवमुक्त किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया गया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण-वितरण तथा धनराशि के उपयोग की पूर्ण सूचना, बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित, शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

(13) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट–शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

(14) उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. द्वारा संघ से सम्बद्ध सहकारी चीनी मिलों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान सम्बन्धी व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी को निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(16) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(17) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 4,50,00,00,000(रूपये चार अरब पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 024 लेखा शीर्षक 6860041010300 उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-32-X-2023-24 दिनांक:23-6-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शेषनाथ

विशेष सचिव

संख्या-5/2023/I/338867/2023(1)/002-46-2002-003-2-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
3- आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र. प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय, आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र., लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शेषनाथ

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।